to ensure compliance with the safety rules for construction of buildings; and

(e) if so, the details of action taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN) : (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

अड़कपुर बाग मोची, नई दिल्ली में भूमि का सर्वेक्षण

3605. **श्री धूलेश्वर मीणा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 जून, 1986 को गांव अड़कपुर बाग मोची, नई दिल्ली में गांववासियों की उपस्थिति में और उनके सहयोग से भूमि का कोई सर्वेक्षण किया गया था और क्या इस सर्वेक्षण रजिस्टर के अनुसार "चुल्हा टैक्स" देने वाले व्यक्तियों और उनके बेटों तथा पोतों के लिए अलग-अलग भूमि-खण्ड निर्धारित किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण रजिस्टर के अनुसार इन चूल्हा-टैक्स देने वाले व्यक्तियों, इन के बेटों और पोतों का कितने-कितने क्षेत्रफल भूमि पर कब्जा है और उनके नाम, राशन कार्ड नं. और मकान नम्बर क्या-क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरसोली मारन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था । तथापि, इस स्थल पर भूमि का कोई प्लाट उद्दिष्ट नहीं किया गया है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

[**देखिए** परिशिष्ट 155, अनुपत्र संख्या-133]

Production consumption and import of fertilizers

3606. SHRI KAMAL MORARKA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) what had been the production, consumption and imports of fertilizers during 1989-90;

(b) whether it is a fact that there were heavy imports during 1989-90; and

(c) if so, what concrete measures have been taken to step up production of fertilizers in the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI UPENDRA NATH VERMA) : (a) The provisional figures for production, consumption and imports of nitrogen, phosphatic and potassic fertilizers taken together during the year 1989-90 was 85.41 lakhs M.T., 115.16 lakhs M.T. and 31.14 lakhs M.T., respectively.

(b) Yes, Sir.

(c) To step up production of fertilizers from old plants several schemes for revamping, modernisation, installation of captive power plants, etc. are being formulated/implemented. Besides, for meeting the demand of nitrogenous fertilizers, the Working Group set up by the Planning Commission for the formulation of Eighth Plan has suggested expansion of three existing larged sized gas based ammonia-urea plants along the HBJ pipeline, in addition to the completion of three projects under implementation. India does not have significant source of phosphatic raw material and practically the entire requirement is met by either import of raw materials or intermediates for producing the phosphatic fertilizer indigenously or importing the fertilizer itself. The Working Group has recommended 85% self-sufficiency in phosphatics by the first method and has recommended setting up of DAP plants with a total capacity of 4.5 lakhs tonnes in terms of P_2O_5 and nitro-phosphates plants with a total capacity of 1.5 lakh

tonnes of P_2O_5. However, the requirements of potassic fertilizers are met entirely by imports as there are no known sources of this material in the country.

Assistance from Japan for important projects

3607. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government are likely to receive Rs. 100 crore equivalent of Yen assistance from Japan for its important projects;

(b) if so, the details of the projects on which these would be spent;

(c) under what terms and conditions Japan has agreed to extend assistance; and

(d) the details of the projects likely to be completed with this assistance ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) to (d) The Government of Japan through their agency Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) are giving financial assistance to Govt. of India for the projects selected for this purpose. Following two projects of the Indian Railways are presently being financed by OECF:

(i) The OECF extended a loan of Japanese Yen 4.8 billion (about Rs. 20 crores) on 23-02-1983 towards construction of Calcutta Metro Railway Project (Phase-II) from Shyambazar Station to Esplanade station. The loan stipulated interest charge at the rate of 2.75% per annum. The loan is repayable in 20 years.

(ii) The OECF on 27-03-1990 had extended a loan of Japanese Yen 1.256 million (Rs. 14.2 crores approximately) towards Rolling Stock Workshop Modernisation Project (I) which cover Jamalpur and Perambur Workshops. The loan stipulates interest charges at the rate of 2.5% per annum. The loan is repayable in 20 years.

चीनी की उत्पादन लागत

3608. **श्री बलराम सिंह यादव** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अगस्त, 1990 के "द फाइनेन्शियल एक्सप्रेस" में "इण्डस्ट्री पुट्स लास एट रूपिज 300 करोड़" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चीनी की उत्पादन लागत के बारे में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो 1990-91 के दौरान चीनी की उत्पादन लागत कितनी होगी और क्या चीनी के उपभोक्ता मूल्य युक्तिसंगत हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बी. आई. सी. पी.) ने पहले जांच की थी और इसकी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की जिसमें 1987-88 से 1989-90 के मौसमों के लिए लेवी चीनी की एक्स फैक्ट्री कीमतों की गणना के लिए परिवर्तन लागत सूची का उल्लेख किया है ।

(ग) उत्पादन की वास्तविक लागत विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होती है तथा यह राज्य में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा भुगतान की गई गन्ने की कीमत, गन्ने से चीनी की प्राप्ति, मौसम की अवधि, प्लाट एवं मशीनरी का आकार, मियाद और हालत, तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षता आदि पर निर्भर करती है । सरकार ने औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से विभिन्न क्षेत्रों के लिए विविध पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए 1990-91, 1991-92, 1992-93 मौसम के लिए मूल परिवर्तन लागत सूचियां सुझाने का अनुरोध किया है । लेवी चीनी की खुदरा कीमत 1-1-89 से 5.25 रु. प्रति कि. ग्रा. रही है । खुले बाजार में मुक्त बिक्री की चीनी की कीमतें भी उचित हैं ।